विरोधाभास ◆ देश में गरीबी के पांच आकलन हैं, जिनके आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते

गरीबी के सवाल पर उलझे हैं आंकड़े

गरीबों को निशुल्क खाद्यान्न देने के लिए पहले आंकड़े इकट्ठा करने के योजना आयोग के फैसले पर बवाल मच गया है। आधिकारिक रूप से शहरों में रहने वाले गरीबों की संख्या 1.4 करोड़ है। जिसमें से एक चौथाई के पास दोपहिया वाहन है। एक तिहाई के पास कलर टेलीविजन है और दो तिहाई के पास प्रेशर कुकर है। साथ ही लगभग पांच में से एक स्नातक या इससे ऊपर की औपचारिक शिक्षा प्राप्त है। इस तरह से इस बात को लेकर संशय पैदा हो गया है कि वास्तव में गरीब कौन है? इस तरह के कुछ संशयों से निपटा जा सकता है अगर राष्ट्रीय स्तर पर आय संबंधी समयबद्ध आंकड़े लिये जाएं।

एनसीएईआर ने इस संबंध में काम करके यह दिखा दिया है कि ऐसा किया जा सकता है। 1960 में डांडेकर और रथ ने कैलोरी के आधार पर गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा बताया था। लेकिन तब से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में बहुत बदलाव आ चुका है। देश में अलग-अलग समितियों द्वारा पांच गरीबी अनुपात बताए गए हैं। योजना आयोग ने अपने आंकड़ों में इसे 21.8 फीसदी और 27.5 फीसदी बताया है। अर्जुन सेनगुप्ता समिति ने यह आंकड़ा 78 फीसदी बताया है। विश्व बैंक देश में गरीबी का अनुपात 42 फीसदी बताता है जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति ने देश में गरीबों की संख्या 37.2 फीसदी बताई है। देश में यह बहस का एक बड़ा मुद्दा है कि गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का निर्धारण वास्तव में किस तरह से किया जाए।

एनसीएईआर ने अपने आंकड़ों में इन पांचों निष्कर्षों को शामिल किया जिससे गरीब परिवारों का सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का पता लगाया जाए। यह तथ्य सामने आया है कि गरीब लोग अपने कुल खर्च का लगभग 61 फीसदी भाग अपने भोजन पर खर्च करते हैं। अगर योजना आयोग के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो यह तथ्य निकलकर सामने आता है कि गरीब लोग अपने कुल खर्च का केवल 5 फीसदी भाग चिकित्सा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। इसका साथ ही शिक्षा पर उनका कुल खर्च 5.7

लेखक एनसीएईआर में मैक्रो कंज्यूमर रिसर्च के डायरेक्टर हैं। गरीबी निर्धारण करने के सवाल पर उनका यह लेख।

राजेश शुक्ला

फीसदी रहता है। हालांकि कुछ आंकड़ों में शिक्षा का खर्च 6.2 फीसदी भी बताया गया है। इस बारे में यह एक महत्वपूर्ण दलील दी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था की जाए और ये सुविधाएं गुणवत्तायुक्त भी हो। ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की हालत इतनी खराब है कि गरीब लोगों को निजी ट्यूशन पर काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं जिससे उनका बजट गड़बड़ा जाता है।

अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की सही और गुणवत्तायुक्त व्यवस्था की जाए तो इससे काफी लाभ मिल सकता है। आंकड़ों से यह बात भी सामने आई है कि गरीबी घटने में अशिक्षित गरीबों की संख्या बढ़ी है, जबकि स्नातक स्तर तक पढ़े लिखे गरीबों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। गरीब लोगों की आय का मुख्य स्रोत मजदूरी है और केवल 10 फीसदी गरीबों को ही तनख्वाह मिलती है। एनएसईयूएस द्वारा माने गए 78 फीसदी गरीबों में से आठ फीसदी लोगों के पास रेफ्रिजरेटर है।

ये आंकड़े गरीब और सामान्य लोगों के बीच की रेखा को तय करने में संशय पैदा कर रहे हैं। जबकि विश्व बैंक के आंकड़ों में कहा गया है देशके गरीबों में से केवल 2 फीसदी लोगों के पास ही रेफ्रिजरेटर है और केवल 10 फीसदी लोगों के पास रंगीन टीवी है। विश्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि केवल 25 फीसदी लोगों के पास प्रेशर कुकर है जबकि एनएसईयूएस के आंकड़ों के मुताबिक देश के 41 फीसदी लोगों के पास अपना प्रेशर कुकर है। ये आंकड़े इस बात को भी दर्शाते हैं कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की

तरह असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। और असमानता का यह आंकड़ा चीन, हांगकांग, सिंगापुर और अमेरिका जैसे विकासशील और विकसित देशों के बराबर पहुंच गया है। हालांकि अगर आय के आधार पर आंकड़े लिये जाएं तो तस्वीर और ज्यादा साफ हो सकती है।

भारत जैसे बहु- सांस्कृतिक और बहु मतावलंबी देश में आय के आधार पर आंकड़े जारी करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इससे योजनाएं बनाने में सफलता मिलेगी। देश में तीन बीपीएल जनगणना आयोजित की गई है जो 1992, 1997 और 2002 में आयोजित की गई थी। साथ ही 2011 में हो रही बीपीएल जनगणना का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमें देश में गरीबों के बारे में बहुआयामी सूचनाएं जुटाने के लिए नए रास्ते तलाशने की जरूरत है जिसे देशके ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय आधार पर भी गरीबों के बारे में पता लगाया जा सके।

साथ ही यह देश की राजनैतिक अर्थव्यवस्था के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों को अपने विकास कार्यक्रम चलाने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही अगर ऐसा होता है तो बीपीएल पर चल रही बहस में भी नए तथ्य जुड़ेंगे। इससे देश के कमजोर वर्ग के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की दिशा भी सुधारी जा सकती है। यह बात स्पष्ट है कि देश में गरीब लोगों की सही पहचान करने की जरूरत है। उनके सामाजिक आर्थिक विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है। देश में गरीब लोगों और सामान्य लोगों के बीच के अंतर की रेखा स्पष्ट करने की जरूरत है। उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं देने की जरूरत भी है। अगर ऐसा होता है तो देश में गरीबी भी मिटेगी और यह विकास की दिशा में भी आगे बढ़ेगा।